भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं बन्दोबस्त कार्य

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वव्यापी उपयोगिता के मद्देनजर भू-अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण सहित समग्र भूमि प्रबंधन व्यवस्था में इसे समाहित करते हुए एक व्यापक भूमि संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू-अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण, खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितों की रक्षा की जाती है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त विधेयक, 2011 के द्वारा राज्य के समस्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के भू-खंडो का आधुनिक तकनीक से अद्यतन खतियान तथा मानचित्र तैयार किया जाएगा।

राष्ट्रीय भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम(THE NATIONAL LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME –NLRMP) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित एवं स्वीकृत योजना है। इसके अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है।

NLRMP में निम्नलिखित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है:-

(i) भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण 100% केन्द्रीय अनुदान पर आधारित योजना है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम किए जाने है:-

(a) डाटा इन्ट्री/री-डाटा इन्ट्री/डाटा कनवर्जन

(b) जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर डाटा केन्द्रों की स्थापना

(c) राजस्व कार्यालयों के बीच अन्तः सम्बद्धीकरण (Interconnectivity) एवं

(d) सर्वे मानचित्रों की डिजिटाईजेशन।

(ii) आधुनिक तकनीक से रिविजनल सर्वे तथा सर्वे एण्ड सेटलमेंट अभिलेखों का अद्यतीकरण (50-50% मैचिंग ग्रांट पर आधारित)।

(iii) अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार/भू-अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण (50-50% मैचिंग ग्रांट पर आधारित)।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अनुदान/अंशदान के रूप में 3173.12 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया है। राज्य योजना मद से भी 3210.83 लाख रूपये उपलब्ध कराए गए है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर के माध्यम से भू-अभिलेखों का संधारण, अद्यतीकरण तथा अद्यतन अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रति आम रैयतों को उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के द्वारा वर्षो पूर्व संधारित भू-अभिलेखों को अद्यतन करते हुए इसे सी0डी0 में संधारित किया जायगा क्योंकि हस्तलिखित अभिलेख लगातार इस्तेमाल में लाए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे है।

पूर्व में संचालित भू-अभिलेखो के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विगत साढ़े चार वर्षो में राज्य के कुल 45740 राजस्व ग्रामों में से 21906 राजस्व ग्रामों के डाटा इन्ट्री का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य में कुल 485.93 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

राज्य के 516 अंचलों में कम्प्यूटर के माध्यम से खतियान के संधारण, अद्यतीकरण तथा वितरण के उद्देश्य से केन्द्रीय अनुदान की राधि 1960.80 लाख रूपये बेलट्राॅन को उपलब्ध कराते हुए हार्डवेयर की आपूत्ति, अधिष्ठापन, वायरिंग एवं नेटवर्किंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक अंचल में एक-एक डाटा इन्ट्री आॅपरेटर बेलट्राॅन के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। भविष्य में आॅन लाईन दाखिल- खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए डाटा आॅन लाइन करने की योजना है।

सर्वे मानचित्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी अंचल के 1152 सर्वे मानचित्रों को डिजिटाइज्ड किया गया। पुनः दूसरे चरण में भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर जिले के 14672 सर्वे मानचित्रों को खतियान के डाटा के साथ इंटिग्रेट करने की भी योजना है। उपर्युक्त चार जिले के सभी अंचलों में डिजिटाईजेशन कार्य हेतु साॅफ्टवेयर स्थापित किया जाएगा जिसके फलस्वरूप सुलभता से राजस्व मानचित्रों की आपूत्ति की जा सकेगी। सम्प्रति डिजिटाइज्ड मानचित्रों का मूल मानचित्रों से सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है।